भोला यादव उर्फ भोला कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 का आपराधिक विविध संख्या 10433

28 मार्च, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विपक्षीगण को उनके आपराधिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227—उन्मोचन/डिस्चार्ज—पुलिस ने विपक्षीगण संख्या 2 से 5 के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया; और विद्वान् न्यायालय ने उन्हें उनके आपराधिक दायित्व से उन्मोचित/डिस्चार्ज कर दिया—संपूर्ण केस डायरी में विपक्षीगण संख्या 2 से 5 की मिलीभगत के बारे में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है—जांच के दौरान प्राप्त सामग्री से यह पता चला है कि केवल पक्षों के परिवारों के बीच कई मामलों के लंबित होने के कारण, विपक्षीगण के विरुद्ध संदेह उत्पन्न हुआ है—जांच के दौरान, ऐसा कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे पता चले कि विपक्षीगण संख्या 2 से 5 के बीच कोई षड्यंत्र था।

निर्णीत: जांच के दौरान प्रासंगिक समय और घटना की तारीख पर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 5 घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और न ही ऐसा कोई सबूत आया है कि सह-आरोपी व्यक्तियों के बीच विचार एक जैसे थे—पक्षों के बीच कुछ विवाद था, यह विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 5 के खिलाफ कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता—आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है—याचिका खारिज किया गया।

(पैराग्राफ 6 से 8)

न्याय दृष्टान्त

योगेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 10 एससीसी 394; पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

उन्मोचन, आपराधिक दायित्वों से उन्मोचन।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान ए.डी.जे.-IV, बाढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1034/2019 में पारित आदेश से, जो घोषवारी पी.एस. कांड संख्या 66/2017 से उत्पन्न हुआ था, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 302, 120बी, 201 और 34 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत था, जिसके द्वारा विद्वान निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 5 की ओर से दायर याचिका को अनुमति दी है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 5 को उनके आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री मनोज कुमार पांडे, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री भरत लाल, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक विविध संख्या 10433

थाना मामला संख्या-66 वर्ष-2017 थाना-घोसवरी, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

भोला यादव उर्फ भोला कुमार, पिता- हरि गोप उर्फ हरि यादव, निवास-गाँव- गिलानी, थाना- सारे, जिला-नालंदा

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. रामावतार यादव उर्फ रामोतार यादव, पिता- किशोरी यादव, निवास-गाँव- गिलानी, थाना.-सारे, जिला-नालंदा
3. भुनेश्वर यादव, पिता- किशोरी यादव, निवास-गाँव- गिलानी, थाना.-सारे, जिला-नालंदा
4. शिशुपाल कुमार, पिता- भुनेश्वर यादव, निवास-गाँव- गिलानी, थाना.-सारे, जिला- नालंदा
5. सुबे यादव, पिता- गांडू यादव, निवास-गाँव- गिलानी, थाना- सारे, जिला-नालंदा

..... विरोधी पक्ष/ओ

==========

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनोज कुमार पांडे, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री भरत लाल, एपीपी

==========

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह

मौखिक आदेश

2 28-03-2024 1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान ए. पी. पी. को सुना ।

2. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर किया गया है, जिसमें घोषवारी थाना मामला संख्या 66/2017 से उत्पन्न सत्र विचरण संख्या 1034/2019 में विद्वान ए डी जे चतुर्थ, बाढ़ की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी, 201 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है, जिसके तहत नीचे दी गई विद्वान अदालत ने विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 की ओर से सी.आर.पी.सी की धारा 227 के तहत दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 को उनके आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 16.10.2017 को, इस याचिकाकर्ता ने घोश्वरी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि 15.10.2017 को लगभग 06:00 बजे अपराह्न, ग्राम- समाचक के निवासी रामू पासवान, अपने ईंट भट्टे पर आए और याचिकाकर्ता के छोटे भाई शशिभूषण यादव को मोटरसाइकिल पर ले गए। इसके बाद, याचिकाकर्ता का छोटा भाई मोटरसाइकिल पर गया था लेकिन वापस नहीं आया और बाद में, अगली तारीख को, इस याचिकाकर्ता के भाई का शव एन.एच. 82 के पास एक खाई में मिला। याचिकाकर्ता (सूचनादाता) को संदेह है कि पुरानी दुश्मनी के कारण, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 सहित सभी प्राथमिकी में नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने याचिकाकर्ता के भाई की हत्या कर दी। इसके बाद, उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, वर्तमान मामला शुरू किया गया और जांच पर, पुलिस ने विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के खिलाफ अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया

और उन्हें मुकदमे के लिए नहीं भेजा। लेकिन, विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट से भिन्न होते हुए, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दंडनीय अपराध की धारा 272, 120बी, 201 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत संज्ञान लिया है ।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 06.01.2022 का आदेश याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया है। इस संबंध में, वह प्रस्तुत करता है कि दिनांक 06.01.2022 की वाद सूची के मात्र अवलोकन से ही ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई की अगली तारीख 09.03.2022 को तय की गई थी, लेकिन बाद में, वाद सूची पर ऊपर से दुबारा लिख के इसे हटा दिया गया है और उसके बाद नीचे की विद्वान अदालत ने विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के पक्ष में विवादित आदेश पारित किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना उन्हें उनके आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया है। इसके बाद वह प्रस्तुत करते है कि इस आधार पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 को मामले से क्यों बरी किया गया है और इस तरह, विद्वान निचली अदालत ने घोर त्रुटि की है और आरोपमुक्त करने का आदेश दिनांक 06.01.2022 रद्द करने के लिए उपयुक्त है।

5. हालाँकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. पी. पी., विवादित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी सामग्रियों पर चर्चा करने के बाद, पक्षों को सुनने के बाद और याचिकाकर्ता को पर्याप्त और उचित अवसर देते हुए, आरोप मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। इसके बाद वह प्रस्तुत

करते हैं कि जाँच के दौरान, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के खिलाफ जो एकमात्र सामग्री आई है, वह यह है कि घटना की कथित तिथि पर, वे अपने-अपने घरों में मौजूद नहीं थे। पूरे मामले की डायरी में विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 की संलिप्तता के बारे में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्त रामू पासवान ने भी अपने इकबालिया बयान में विरोधी पार्टी संख्या 2 से 5 पर साजिशकर्ताओं के रूप में आरोप नहीं लगाया है या उनका नाम नहीं लिया है। यहां तक कि सह-अभियुक्त रामू पासवान के मोबाइल का सी.डी.आर. भी सह-अभियुक्त रामू पासवान और विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के बीच किसी भी बातचीत का खुलासा नहीं करता है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि जाँच के दौरान यह सामने आया है कि घटना की कथित तिथि पर, विरोधी पक्ष संख्या 3, अर्थात् भुनेश्वर यादव, जो एक अंचल अधिकारी हैं और जो मुंगेर में तैनात थे और अपराध के प्रासंगिक समय पर उन्हें आर.डी. और डी.जे. कॉलेज, मुंगेर में स्टेटिक मजिस्ट्रेट-सह-पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था, और उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएँ और प्रश्न पत्र एकत्र किए और उन्हें सील कर दिया और उन्हें दो ट्रक पर लोड कर दिया और लगभग 07:30 बजे अपराह्न परीक्षा केंद्र पर जमा कर दिया और उसके बाद, 16.10.2017 को वह कार्यालय में पूर्णतः मौजूद थे। इसी तरह विरोधी पक्ष संख्या 5, अर्थात् सुबे यादव, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष उपस्थित थे और 18.10.2017 को जमानत प्राप्त की। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 और सह-अभियुक्त रामू पासवान, जिनके साथ मृतक को आखिरी बार देखा गया था, के बीच कोई सबूत या सामग्री या साजिश नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि जाँच के

दौरान यह सामने आया है कि मृतक के परिवार और विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के परिवार के बीच कुछ मामले लंबित हैं, और इसी आधार पर, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के खिलाफ संदेह उठाया गया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता (सूचनादाता) के भाई की हत्या की होगी। विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***(2008) 10 एस. सी. सी. 394*** में रिपोर्ट किए गए ***योगेश बनाम महाराष्ट्र राज्य और (2010) 2 एस. सी. सी. 398*** में रिपोर्ट किए गए ***पी. विजयन बनाम केरल राज्य*** के मामलों में पारित निर्णयों पर भी भरोसा किया है ।

6. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की दलील सुनी और विवादित आदेश का अध्ययन किया। सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए, अदालत के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूत को स्थानांतरित करने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि क्या आरोपी के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है या नहीं। यह केवल तभी होता है जब अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री रखी जाती है जो आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करे, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, अदालत आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी। इस मामले में, जांच के दौरान आई सामग्री से यह सामने आया है कि केवल पक्षों के परिवारों के बीच कई मामले लंबित होने के कारण, इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संदेह उठाया गया है। जाँच के दौरान, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं आई है कि एक ओर विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 और सह-अभियुक्त रामू पासवान के बीच कोई साजिश थी। इस मामले में जाँच के दौरान यह भी सामने आया है कि घटना

के प्रासंगिक समय और तिथि पर, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, और न ही कोई सबूत आया है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच मन का मिलान हुआ था। केवल इसलिए कि पक्षों के बीच कुछ विवाद था, यह विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 के खिलाफ कार्यवाही करने का आधार नहीं हो सकता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री केवल संदेह को जन्म देती है, जो गंभीर संदेह से अलग है। निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त करते समय केस डायरी की पूरी सामग्री के साथ-साथ आरोप पर भी ध्यान दिया है ।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे वर्तमान आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है। आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

8. तदनुसार, यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अनय/शशांक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।